12.11 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Total collapse of power system in Delhi and in northern States of Punjab, Haryana, Rajastan and Uttar Pradesh on 19th July, 1984

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> दिल्ली में तथा उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरयाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में 19 जुलाई, 1984 को विद्युत व्यवस्था के पूर्णत: ठप्प हो जाने और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

12.12 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

THE MINSITER OF STATE IN THE MINSITRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : Sir. there was a grid disturbance on 19. 7. 1984 at 8 p. m. in the Northern Grid. The disturbance caused total power failure in Delhi and in parts of Haryana, Rajasthan. Western U. P. and Punjab.

Preliminary reports indicate that there was a severe voltage dip in Delhi area which caused tripping of tho generating units at Badarpur and Indraprastha stations. The inter-connecting transmission lines between Bhakra and Delhi also tripped. Power generation at I. P. station at that time was about 190 MW.and at Badarpur about 300 MW. Delhi was importing about 200 MW from BBMB system. and U. P. was injecting about 100 MW of power into the Delhi system.

The transmission lines in Western U. P. also tripped on power swing resulting in separation of the Western parts of the State from the Eastern areas. Three thermal units at the Harduaganj power station and one unit at the panki thermal power station in U. P. also tripped. However, the thermal power stations at Obrv and Singrauli were not affected. In the BBMB system. unit No. 3 at Bhakra tripped while all the other units continued to supply power to punjap, part of Haryana, J&k and Himachal Pradesh. In Rajasthan. generation at the Atomic Power Plant was not affected.

Action was taken to restore the units at the I. P. and Badarpur Stations by availing start-up power supply from U.P. and Bhakra. The first unit at I.P. Station was synchronised at about 9.55 p.m. while the first unit at Badarpur was synchronised at about 10.45 p.m. Other units at these stations were also brought back subsequently. The power supply to various parts of Delhi was restoiny progressively and was normalised shortly after midnight. Eastern and Western U.P. were synchronised by about 9.30 p.m. while the Rajasthan Atomic Power Plant was synchronised with BBMB system at 9.20 p.m.

A number of technical issues have to be sorted out before any conclusions can be reachee regarding the circumstances in which the power failure occurred. Government have, therefore, appointed on the 20th July, 1984, a high level Enquiry Committee under the Chairmanship of Shri A.N. Singh, Chairman, Central Electricity Authority to investigate and identify the causes of the system disturbance and to suggest remedial measures to avoid recurrence of such incidents. The Committee has been asked to submit its report in one

(Shri Arif Mohamad Khan)

month's time and has already started its work.

Members would kindly appreciate that prompt action was taken to bring back normalcy in the Northern Grid and to restore power supply as soon as possible. The cooperation extended by U.P. and BBMB fof immediate spply of start-up power is also commendable. Sir, I would like to assure the Hon'ble Members that measures are being devised to further strengthen the Northern Grid and the Delhi power supply system.

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 19 जुलाई को पूरे उत्तर भारत में बिजली के गुल होने के जो कारण दिए हैं, वे अविश्वसनीय हैं। मैं नहीं मानता कि नार्दन ग्रिड में गड़बड़ होने के कारण पूरे उत्तर भारत में बिजली गुल हो गई। मैं यह भी नहीं मानता कि प्रशासन द्वारा बनाई गई वितरण प्रणाली इतनी मजबूत है कि कोई उग्रवादी उसको फेल न कर सके।

जो जांच समिति बिठाई गई है, उसकी रिपोर्ट तो बाद में जाएगी, मगर स्थिति यह है कि सरकार ने बिजली फेल होने के सही कारणों को छिपाने की कोशिश की है। पहली बार ऐसी घटना हुई होगी कि देश की राजधानी दिल्ली में बिजली गुल हो जाए और राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री निवास और दिल्ली के सब अस्पतालों में बिजली न हो। यह कोई मामूली बात नहीं है। जो जांच समिति गठित की गई है, उसको आदेश देना चाहिए कि वह निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करे। आम लोगों और इस सदन के माननीय सदस्यों को संदेह है कि इस घटना में उग्रवादियों का हाथ था और उन्होंने किन्हीं खास् करणों से एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे उत्तर भारत की बिजली गायब कर दी। इस प्रकार पूरे भारत की बिजली चले जाना सरकार की अक्षमता का सबूत है।

सरकार की बिजली के पारेषण की व्यवस्था इतनी खराब है कि जो चाहे, वह बिजली की सप्लाई को अस्त-व्यस्त कर सकता है। जो उग्रवादी पाकिस्तान और अन्य विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, वे एक इशारे पर पूरे उत्तर भारत की बिजली गुलकर सकते हैं। इससे देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। 36 साल की आजादी के बाद भी बिजली के वितरण की व्यवस्था इतनी निराशाजनक है कि योजना आयोग को इसपर चिन्ता व्यक्त करनी पड़ी है। योजना आयोग ने कहा है कि अगर बिजली के वितरण की यही स्थिति रही, तो हिन्दुस्तान का आर्थिक विकास पिछड़ जाएगा। यह सरकार आर्थिक विकास का टारगेट कभी भी पूरा नहीं कर पाई है।

ऊर्जा मंत्री, श्री शिव शंकर, ने राज्यों में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में चिन्ता व्यक्त की, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन आज स्थिति यह है कि बिजली की योजनाओं पर 48 अरब रुपये खर्च करने का गवर्नमेंट आफ इंडिया का टारगेट था, लेकिन समय पर वे योजनाएं पूरी न होने के कारण उन योजनाओं का खर्च बढ़ कर 66 अरब रुपये होने जा रहा है। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया अपनी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा नहीं कराएगी, तो उसका बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। उसकी कोई भी योजना

समय पर पूरी नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, में यही हालत है। बिहार में तो स्थिति और भी खराब है। वहां पर चित्रकूट योजना पर 1961-62 से काम हो रहा है, लेकिन 22 साल के बाद भी वह पूरी नहीं हुई है।

इस हालत में सरकार देश की बिजली की आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। यह मामला न केवल देश की अर्थ-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि एकता और अखंडता से भी सम्बन्ध रखता है। बिजली की वितरण प्रणाली इतनी कमजोर है कि कोई उग्रवादी एक गोले से पूरे उत्तर भारत की बिजली को खत्म कर सकता है। उस दिन दिल्ली के अस्पतालों में रात के 12 बजे तक बिजली नहीं पहुंची।

मरीजों की स्थिति क्या हुई? यह आवश्यक सेवाएं भी जो हैं उनके लिए भी मैं समझता हूं कि यह कोई मामूली बात नहीं है। पढ़ने के लिए केवल एक लाइन अखबारों में आ गया कि पूरे उत्तर भारत में बिजली गुल हो गई, लेकिन देश की अर्थ-व्यवस्था और देश की अखण्डता व एकता से यह सवाल जुड़ा हुआ है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि इस पर जो जांच समिति आपने बैठायी है उसमें इस के कारणों को छिपाया न जाय जैसे श्वेत-पत्र में भारत सरकार ने कारणों को छिपाने की कोशिश की और सही तस्वीर नहीं आने दी। जांच समिति को आप सख्त आदेश दें कि जो इसके कारण हों उनको प्रकाश में लाएं। अगर इसमें उग्रवादियों का हाथ है, भाखड़ा नहर तोड़ने वालों का हाथ है क्यों कि भाखड़ा से मेन जो बिजली डिस्टर्ब हुई है उसके कारण सारी व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई जिसके सारे हाइड्रोपावर और थर्मल पावर बन्द करने पड़े। आपने जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश से बिजली लेने की कोशिश की और वह आप को मिली।

(व्यवधान)

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस घटना के पीछे उग्रवादियों का हाथ था और अगर हाथ था तो इस जवाब में आना चाहिए था कि इसके पीछे उग्रवादियों का हाथ था। बरहाल मैं समझता हूं कि ऐसी घटना हिन्दुस्तान में आज तक नहीं हुई। विदेशों का उदाहरण मैं नहीं देना चाहता। विदेशों में एक मिनट भी अगर बिजली चली जाय तो इतना सख्त कदम वहां की सरकारें उठाती हैं कि आइन्दा कभी किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती। यहां आपके राष्ट्रपति भवन में बिजली चली जाय, पी एम हाउस में चली जाय यह कोई मामूली बात नहीं है। भविष्य में इन जगहों के लिए आप जैनरेटर से बिजली के जैनरेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं लेकिन जो जन-साधारण हैं जिन को पीने का पानी नहीं मिला, दिल्ली की बस्तियों के अंदर रात के एक बजे तक पानी नहीं मिल पाया उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आप वी आइ पीज के यहां जैनरेटर्स की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन यह मैं फिर माननीय मंत्री जी से दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि सातवीं योजना में जो आप ने विद्युत उत्पादन का लक्ष्य बनाया है और आपने

(श्री जगपाल सिंह)

जो यह चिन्ता राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त की है कि अगले तीन सालों में जो आप का उत्पादन होगा उस से आप देश की बिजली की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे, क्या यह संभव हो सकेगा ? सातवीं योजना में आप ने हाइड्रो पावर के बारे में जो कहा है वह 13590 मेगावाट के उत्पादन की बात कहीं है और तापीय बिजली 1709 मेगावाट उत्पादनकरनेकी बात कही है। मैं जानना चाहूंगा कि इस उत्पादन के बाद कितने हजार मेगावाट बिजली की कमी देश के अंदर रह जायगी ?

एक सवाल में इन्तजामिया दृष्टि से पूछना चाहता हूं। इस घटना के बाद क्या आप ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था राज्यों के पावर स्टेशनों के द्वारा करने जा रहे हैं जिससे अगर एक जगह से बिजली चली जाती है या कोई इस प्रकार का सरप्राइज होता है तो आप उस के द्वारा बिजली की आपूर्ति कर सकें ? ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या आप करने जा रहे हैं ? क्यों कि एक घटना आप के सामने आ गई। पूरे उत्तर भारत से बिजली चली गई तो दिल्ली में कम से कम आप इन्द्रप्रस्थ के अन्दर जो पावर स्टेशंस हैं या दूसरे जो हाइड्रो पावर स्टेशंस हैं उन के द्वारा दिल्ली की आवश्यकता को पूरी कर सकें ताकि प्रदेशों से अधिक बिजली आप को न लेनी पड़े, इस तरह की व्यवस्था आप करें। क्या ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं और अगर करने जा रहे हैं तो इस के लिए क्या योजना आप बना रहे हैं ताकि अगर भविष्य में ऐसी गड़बड़ी हो तो वैकल्पिक व्यवस्था आप के पास रहे जिस से पूरे उत्तर भारत में इस तरह की घटना न घट सके ? इसके अलावा उग्रवादियों के सम्बन्ध में क्या कदम आप उठाने जा रहे हैं ? विशेष रूप से भाखड़ा पर आप विशेष ध्यान रखें और भविष्य में कम से कम दिल्ली को भाखड़ा पर अधिक निर्भर न बनाएं। दिल्ली के लिए सेल्फ-डिपेंट बिजली की सप्लाई के लिए क्या क्या योजनाएं बनाने जा रहे हैं मैं जानना चाहता हूं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय महोदय, 19 जुलाई को बिजली के फेल होने की घटना पर पहले भी सरकार की तरफ से हमने चिन्ता की है। हम इसे बहुत गम्भीर घटना मानते हैं और उसकी गम्भीरता को देखते हुए ही एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है, ताकि वह न केवल उन कारणों की जांच कर सके, जिस की वजह से इतने घन्टे बिजली न होने से उत्तरी क्षेत्र, खास तौर से दिल्ली, प्रभावित रहा, बल्कि भविष्य के लिए भी ऐसे सुझाव दे सके, जिनको लागू करने के बाद इस किस्म की घटना को दोबारा घटने से रोका जा सके। अब चूंकि एकसमिति बनाई जा चुकी है और उसकी जांच करनी है, तो जांच समिति की रिपोर्ट व उस के निष्कर्ष आने के पहले कोई कारण हमारी तरफ बताना बिल्कुल उचित नहीं लगेगा। वैसे भी हमारे विशेषज्ञों का यह मत है कि प्राइमा-फेसी ऐसा लगता नहीं है कि यह किसी उग्र-वादी की शरारतों के कारण बिजली फेल हुई हो। लेकिन अगर फिर भी माननीय सदस्य इतनी निश्चितता के साथ कह रहे हैं तो अगर कोई इस संबंध में सूचना उपलब्ध करायेंगे तो हम उस समिति को कहेंगे

कि वह उसमें विस्तार के साथ जांच करे।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, पारेषण व्यवस्था भी ठीक नहीं है और हम बिजली ठीक से उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर बिजली का विकास, बिजली उपलब्ध कराना, बिजली का पारेषण और वितरण व उत्पादन यह सारा काम राज्य सरकारों के करने का है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से, सैन्ट्रल सैक्टर को मजबूत करने और सुदृढ़ करने और सैन्ट्रल सैक्टर में भी बिजली के उत्पादन का काम जरूर अपने हाथ में ले लिया है।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी परियोजना समय से पूरी नहीं हुई। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार के किसी भी निगम के अन्तर्गत आने वाली कोई भी परियोजना ऐसी नहीं है जो निश्चित समय के बाद पूरी हुई हो। ऐसा तो है कि या तो निश्चित समय पर कमीशन किया गया हो या निश्चित समय से पहले ही उन्हें कमीशन किया गया हो। लेकिन ऐसा एक भी मामला नहीं है कि जहां पर वह समय से आगे हो गई हो। यह मैं सुपर थर्मल पावर की बात कर रहा था। एन.एच.पी.सी. के अन्तर्गत पन-बिजली बनती है। परियोजनाओं में कहीं-न-कहीं देरी हुई है और उसके जियोलोजिकल कारण दिये हैं। वे सब हमें मालूम हैं। उसमें भी प्रशासनिक कमी के कारण देरी नहीं हुई है, बल्कि दूसरी कठिनाइयां वहां उत्पन्न हो गई हैं। उसमें भी पूरी कोशिश है कि उस देरी को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : राजस्थान में समस्या एटोमिक पावर प्लान्ट की है। आए दिन एक और दो यूनिट बन्द रहते हैं। इस पर भी आप काम्प्रिहैंसिव विचार करिए। इसके साथ मद्रास की भी बात। आप कन्सोलिडेटेड व्यूह लीजिए, इन्टीग्रेटेड व्यूह लीजिए, केवल सुपर थर्मल पावर का सवाल नहीं हैं। हम आपके पास आते हैं, आपको चिट्ठी लिखते हैं। सबको प्राब्लम है। आप क्या व्यवस्था आगे के लिए करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं माननीय सदस्य, श्री सतीश अग्रवाल, की बात का स्वागत करता हूं। निश्चय ही सरकार का यही रुख रहा है। हम इन्टेग्रेटेड व्यूह ही लेते हैं। यही कोशिश है कि हमारा कोई भी बिजली का यूनिट हो, चाहे थर्मल हो, चाहे पन-बिजली हो, चाहे न्यूक्लियर हो, बन्द न होने पाए। लेकिन प्रशासनिक कठिनाई मेरे उत्तर देने में हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह बन्द क्यों है। न्यूक्लिर पावर प्लान्ट हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है। उसमें पूरे प्रयास किए जा रहे और कुछ कठिनाई के कारण उसमें कहीं न कहीं परेशानी है, वह अलग बात है। लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं है। वहां भी जो साइंटिस्ट्स हैं, उन विशेषज्ञों का प्रयास है कि प्लान्ट बन्द न होने पाए। उनमें बिजली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके।

इसके अलावा माननीय जगपाल सिंह जी ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में बिजली बन्द हो गई...

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is the main questioner. This is a side track .

(Interruptions)

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): My personal belief is that the States cannot do anything. Something has to be done at the Central level.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I was telling him that he is coming to the main questioner.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEARER : Mr. Agarwal, I did not object to his replying to you. But I said, he is the main questioner.

(Interruptions)

श्री जगपाल सिंह : उस मीटिंग में कहा गया था कि प्रदेशों के वस का काम नहीं रहा है। केन्द्रीय सरकार इस पर पुर्नविचार कर रही है। मैं जानता हूँ कि पुर्नविचार क्या है। यह बात सही है कि राज्यों के बस का यह काम नहीं है, केन्द्रीय सरकार ही इस काम को सम्भालने के लिये काम्पीटैंट है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य का सुझाव है कि प्रदेश सरकार. इस में सक्षम नहीं है. केन्द्रीय सरकार सक्षम हैं। इस में सन्देह नहीं है कि यह भी एक दृष्टिकोण है और जैसा मैंने कल भी बतलाया था कि हमारे मंत्रालय की सलाहकार समिति और इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन योजनाओं के समय पर पूरा करने के लिये और इनके बेहतर कंपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिये, केन्द्रीय सरकार का इस में ज्यादा दखल होना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों का मत है कि यह विषय केन्द्रीय सूची में आना चाहिये, लेकिन जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि प्रदेश सरकारों की तरफ से इस पर आपत्ति की जाती है। माननीय जगपाल सिंह जी ने जो कहा है, मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे सामने दोनों ही दृष्टिकोण हैं यदि हम उनके दृष्टिकोण को मान कर चलें तो कल ही यह कहा जायगा कि प्रदेश सरकारों के जो अधिकार हैं उनको सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है.

श्री जगपाल सिंह : एक मीटिंग में यह कहा गया था...

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उस मीटिंग में इस लिये चिन्ता व्यक्त की गई थी कि कुल मिला कर नीति निर्धारण और समन्वय स्थापित करना केन्द्रीय सरकार का काम है। जहां कहीं यह देखते हैं कि राज्य सरकारें निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर रही हैं, उस में शिथिलता आ गई है, वे पीछे रह गई हैं, वहां हमने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिये हैं। माननीय मंत्री जी ने केवल चिन्ता ही व्यक्त नहीं की है, बल्कि उससे पहले अपने पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकारों का ध्यान भी दिलाया है। मैं इस बात को मानता हूं-बिजली केवल रोशनी देने के लिये ही नहीं, बल्कि विकास के लिये, डवेलपमेन्ट के लिये, पोस्ट एसेन्शियल इन्पुट है। इस पर हमारा पूरा ध्यान है और माननीय सदस्य के जो दूसरे सुझाव हैं उन को भी ध्यान में रख कर ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।

SHRI SATISH AGARWAL : It happened so many times. Have you ever seen this power failure in any country you have visited? Why is it so here, Sir ? I am asking you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. I am not to reply here .

SHRI SATISH AGARWAL : But you can enlighten the House. You have visited so many places abroad. Have you ever come across a power failure anywhere in any country? It is because they are so interconnected with the national grid .

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not expected to reply to your question . .

SHRI SATISH AGARWAL : So, why don't pou think on those lines? Let us have a national grid .

MR. DEPUTY-SPEAKER : You don't participate. Your name is not here .

(Interruptions)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमान, मैं उन देशों से अपनी तुलना नहीं करना चाहता जिन्होंने अपने अपने विकास की दौड़ 200 या 250 वर्ष पहले शुरू की थी। मेरे पास उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अपने विकास की दौड़ हमने 35-36 वर्ष पहले शुरू की थी...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Jagpal Singh and other friends, you know, as you take it up with the Central Government, you must also take it up through your party with the State Governments also. This is a Concurrent subject. Both have to cooperate to achieve the target. Therefore, you should also vehemently take it up with the State Governments .

SHRI SATISH AGARWAL : We should then go to the Assemblies? I do not want to go to the Assembly .

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, it connot be done only by the Central Government, it can be done with the cooperation of State Governments .

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लेकिन मैं यह समझता हूं कि देश की आजादी के बाद हमारे इन्जीनियरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, बिजली के विकास के क्षेत्र में जो कार्य किया है, निश्चित ही वह सराहनीय है। यह बात सही है कि हम अभी तक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाये हैं, लेकिन हमने जितने विकास का रास्ता तय किया है वह अपने आप में सन्तोषजनक है और आगे भी हम इस काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे।

मैं यह भी निवेदन कर दूं 6ठी पंच वर्षीय योजना शुरू करने के पहले हमारी कुल उत्पादन क्षमता 28 हजार मेगावाट थी। 6ठी पंच वर्षीय योजना का अंत आते-आते यह उत्पादन क्षमता 43 हजार मेगावाट हो जायगी और इसे आप इस सन्दर्भ में देखिये कि जहां 1947 के बाद कुल उत्पादन क्षमता 1300+कुछ मेगावाट थी

श्री राजेश कुमार (फिरोजाबाद) : 6ठी पांच वर्षीय योजना का टारगेट क्या था ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप यदि उस के लिये अग्रिम सूचना देंगे तो मैं निश्चित रूप से वह भी बतलाऊंगा। इस वक्त मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि 1300 मेगावाट से कुछ ज्यादा से शुरू कर के आज छटी पंचवर्षीय योजना का अन्त होने पर 43,000 मेगावाट बिजली की क्षमता हमारे पास होगी। यह मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि यह हमारी पूरी जरूरतों को,

(श्री आरिफ मोहम्मद खां)

पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जैसा कि मैंने कल भी कहा था बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक कैपीटल इन्टेंसिव काम है। जितने साधन हमारे पास उपलब्ध होते जाते हैं उतना विकास होता जाता है। माननीय जगपाल सिंह सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहे थे। उस के बारे में मैं अभी सिश्चित आंकड़े नही दे सकूगा लेकिन भारत सरकार इस को महत्व देती है, प्रायरटी देती है और प्राथमिकता के आधार पर बिजली के उत्पादन को और बढ़ाने का काम हम करेंगे।

जगपाल सिंह : छटी पंचवर्षीय योजना में जो ट्रांसमीशन लाइन बिछाने का टार्गेट था, उस में 400 के.वी के 41 परसेंन्ट लाइनें बिछा पाए और 220 के.वी की 51 परसेंन्ट लाइनें आप बिछा पाए। हालांकि ये जो आंकड़े हैं, इन को मैं सही नहीं मानता लेकिन यह जो स्थिति है यह बहुत निराशाजनक हैं। 400 के.वी के टार्गेट का 41 पर सेंन्ट और 220 के.वी के टार्गेट का 51 पर सेन्ट ही आप कर पाए हैं और यह बहुत निराशाजनक हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं ने पहले भी इस संबंध में कहा है कि ट्रान्समीशन लाइन सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो लक्ष्य निर्धारित थे उन में जो हम पीछे रह गये हैं, उन की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है और हम ट्रान्समीशन सिस्टम को और स्ट्रेंग्थन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष जी, 19 तारीख को देश के अन्दर कई हिस्सों में बिजली गुल रही और कई घंटे तक अंधेरा रहा, इस पर देश मंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की और उस के लिए एक समिति भी गठित की है। मैं उम्मीद करता हूं कि जांच समिति अपना कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लेगी और कुछ खास मुद्दों पर भी वह अपनी सिफारिश करेगी, जिन पर सरकार जल्दी अमल करे पर इस सब के बावजूद, बिजली का सवाल हमारे देश में जनता का सवाल है। यह तो ठीक है और मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1300 मेगावाट से कुछ ज्यादा से 43,000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन बढ़ाया है पर इस पर हम संतोष नहीं व्यक्त कर सकते प्रश्न यह है कि इस बात को स्वीकार करने में मंत्री जी की भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बिजली की टोटल व्यवस्था नाकारा है। उस के कारण अनेक हैं और उन कारणों में राज्य सरकारों के पावर बोर्डों की जो हालत है, जो मिसमैनेजमेंट है, वह सब से बड़ा कारण है। पर यह कह कर हम देश के विकास की रफ्तार को रोकने का बाहाना नहीं ढूंढ सकते। आज कृषि के उत्पादन के लिए बिजली चाहिए, आज उद्योगों के लिए बिजली चाहिए। हमारे अनेक पब्लिक सेक्टर इसलिए घाटे में जाते हैं और बदनाम होते हैं क्योंकि बिजली वहां नहीं मिलती। चाहे स्टील की बात देख लें, चाहे फर्टीलाइजर्स की बात देख लें और चाहे ड्रग सेक्टर की बात देख लें। मैं पब्लिक सेक्टर की बात करता हूं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहां पर हम कर रहे हैं और आपने स्टैन्डबाई ट्रान्सफार्मर्स की इजाजत दी, पावर जनरेटिंग सेट की इजाजत दी है और और उन में ह्यूज

इन्वेस्टमेंट कर के इस की आप आपूर्ति कर रहे हैं। यह अपने आप में देश के लिए एक चिन्ता का सवाल है। इस मामले में सब से बड़ी बात यह है कि मंत्री महोदय आपको कोई न कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा, जो बीमारियां हैं उनका इलाज करना पड़ेगा। यह तो सही है कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने हमारे सुपर थरमल पावर स्टेशन समय से खड़े कर दिये। लेकिन जो आम शिकायतें आती हैं और जिनका कि आज तक कोई इलाज नहीं हुआ उनमें एक तो यह है कि कोल इंडिया कोयला ठीक ढंग का सप्लाई नहीं करता। यह एक आम शिकायत है।

अब तो कोयले और बिजली दोनों के विभाग एक ही मिनिस्ट्री के नीचे है, उसके एक ही मिनिस्टर हैं। पहले तो यह शिकायत होती थी कि कोल इंडिया आपके अण्डर में नहीं हैं। अब एनर्जी मिनिस्टर इज वद। इस के बावजूद क्या वजह है कि कोयले की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकती है? अगर कोयले को वाश करने की जरूरत है तो क्यों नहीं वाश करने के लिए प्रोग्राम बनता है? मैं यह जानना चाहूंगा कि कोयले की अच्छी क्वालिटी की आपूर्ति के लिए आपने क्या कदम उठाया है? कोयले की सप्लाई का कारण पैदा कर के बिजली के उत्पादन में जो गड़बड़ी बताई जाती है, क्या कभी आपने इस कारण को अनेलाईज किया और उसतो अनेलाईज करने के बाद क्या कदम उठाये?

आपने उस दिन बिजली चले जाने के बारे में कहा कि यह सेबोटेज के कारण नहीं हो सकता। आपने कहा कि वह पावर यूनिट फेल हो गया, यह पावर यूनिट फेल हो गया, ट्रिपिंग हो गई। इन सब का मतलब तो यह है कि मैनेजमेंट का दोष था, टेक्निकल लोगों का दोष था। इस सब के बारे में आप क्या कदम उठाने के लिये तैयार हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि मैनेजमेंट का भी दोष है।

यह प्रश्न भी हमारे सामने है कि पावर सप्लाई में कुछ बाते ऐसी हो रही हैं जिनको कि हम बहुत पहले रोक सकते थे। यह ठीक है कि हमारे पास रिसोर्सिज नहीं हैं। लेकिन आप पावर का एफीशियेन्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इससे ही आप बहुत अधिक रिसोर्सिज बना सकेंगे। एक परसेन्ट पर मेगावाट थरमल मावर से ही आप करीब-करीब 6 अरब रुपये का इन्वेस्टमेंट बचा सतते हैं। जब आप यह कर सकते हैं तो क्या आप उसके लिए कदम उठा रहे हैं? उसके लिए आपकी क्या योजना है? ये सब चीजें शार्ट टर्म और लांग टर्म प्लानिंग के लिए आपका क्या चिन्तन है?

हिन्दुस्तान में, शायद, पावर के डिस्ट्रिब्युशन और ट्रांसमीशन पर जितने लासेज होते हैं वे हाएस्ट हैं। 22, 23 और 24 परसेंट तक ये होते हैं। मेरी स्टेट में तो, जैसा कि मैं सुनता हूं, 30 से 32 परसेंट तक होते हैं। दूसरी स्टेट्स में कम्पेरेटिवली ये लासेज 7, 8, 10 परसेंट से ज्यादा नहीं हैं। इसके बारे में यह दलील को जा सकती है कि यहां बहुत लम्बी लाईन हैं। क्या उन लाइनों के सिस्टम को स्ट्रेंगदन नहीं किया गया है? पिछले 10-15 सालों से मैं यह सुनता आ रहा हूँ और यह सुनते-सुनते हमारे कान पक गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपकी शार्ट टर्म और लांग टर्म प्लानिंग क्या है? आपने इसके लिए क्या किया है? इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमैंट की जरूरत नहीं है. किसी

(श्री नवल किशोर शर्मा)

बड़े टेक्नीकल नो-हाऊ की जरूरत नहीं है। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। आपने इस दिशा में क्या टारगेट फिक्स किये हैं। अगर आप ट्रांस मीशन लाईन की प्रणाली को बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि प्लांट लोड फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं तो आज बिजली का अभाव है मैं तो इसे अकाल कहूंगा, वह अकाल शायद इन दो बातों से नहीं रहेगा। बिजली के सवाल के साथ ही दिल्ली में जो यह घटना हुई और दिल्ली के आस पास जो यह घटना हुई, यह घटना आंखें खोलने वाली होनी चाहिए। यह भी गनीमत थी कि ऐसे मौकों पर एंटी सोशल एलीमेंट्स फायदा नहीं उठा सके। लेकिन अगर कहीं वे ऐसे मौके पर...

एक माननीय सदस्य : आपने उनको कहा नहीं होगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह काम हमने आपको सौंप रखा है और आप इस काम में माहिर भी हैं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन सारी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे मित्र सतीश अग्रवाल ने अभी राजस्थान की चर्चा की। बड़ी अजीब बात है कि जब भी राजस्थान के बारे में एटा-मिक पावर की बात आती है तो यह कह कर आप चुप हो जाते हैं कि यह मंत्रालय हमारा नहीं है। यह आर्गूमेंट हमको कन्वींस नहीं करता। गवर्नमेंट एक है, सब की संयुक्त जिम्मेदारी है। बड़े अफसोस की बात है कि दो एटामिक पावर स्टेशन कभी भी एक साथ एक दिन भी नहीं चले। पिछले पांच सात सालों का यह हाल है। दुर्भाग्य से हमारे पास हाइड्रल पावर की व्यवस्था नहीं है। दूसरी स्टेट्स से हमारे, इंटर-स्टेट्स एग्रीमेंट होते हैं। वे स्टेट्स पावर को कंट्रोल करते हैं। एग्रीमेंट के बावजूद वायलेट होता है। हमको बिजली नहीं मिलती है। आपको कहते हैं तो आप कहते हैं कि स्टेण्ट सैंटर है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन स्टेट्स की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब पोटेंशल है और जहां हालत खराब है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि हम क्या कर सकते हैं, यह तो स्टेट का सवाल है। मैं तो एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस में विरोधी दल के लोग भी बार-बार मांग करते रहे हैं और आपकी कंसलटेटिव कमेटी ने भी यह यूनेनिमस फैसला किया है कि इलेक्ट्रिसिटी को सेंटर के पास आना चाहिए। आप लाइए एक बिल और इसमें अमेंडमेंट कीजिए। इसके बाद ये अगर कहते हैं कि केन्द्र के पास ज्यादा अधिकार आ रहे है तो इनको इक्सपोज होने दीजिए। आप डरते रहते हैं। इनको नंगा होने दीजिए। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनको एक्सपोज कीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : सरकार करना ही नहीं चाहती।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, नंगा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। क्या यह अनपार्लियामेंट्री नहीं है ?

MR. DEPUTY SPEAKER : He is on a different subject.

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा कह दिया। जो पहले ही नंगा हो उसको क्या नंगा करेंगे। मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस सारे मामले पर विचार करना चाहिए। मेरे जो प्रश्न हैं कि छटी पंचवर्षीय योजना के टारगेट को कितना एचीव किया। ट्रांसमीशन लाइन के बारे में क्या स्थिति रही। स्टेट-वाइज परफारमेंस क्या रही। कोयले की स्थिति क्या रही ? अभी जानकारी नहीं है तो बाद में जवाब भिजवा देवा। यह बहुत ही चिंता का विषय है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 1984-85 के लिए आपका बिजली उत्पादन का लक्ष्य क्या है ? उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपकी क्या आकाक्षाएं है ? ट्रांस-मिशन लाईन के लिए क्या आकांक्षाएं हैं ? एक बात बार-बार उठती है कि बी.एच.इ.एल. से जो मैटीरीयल सप्लाई किया जाता है, वह खराब है। "भेल" वाले बराबर यह कहते हैं कि हमारी मशीनरी में कोई खराबी नहीं है। इस विवाद का हमेशा के लिए हल करने की दिशा में आपने क्या कदम उठाया है ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि बी.एच. इ.एल. एक महत्वपूर्ण पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग है। इसलिए, इसमें सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, यह देखना चाहिए ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नवल किशोर शर्मा जी ने जो चिंता व्यक्त की है, उससे हम सहमत हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकें। राजस्थान एटोमिक पावर प्लान्ट के बारे में सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैंने जिम्मेदारी से बचने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, निश्चित ही मिली-जुली जिम्मेदारी है। मैंने सिर्फ यह कहा था कि उसकी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मेरे लिए उसके बारे में विस्तार से यहां बता पाना संभव नहीं हो सकेगा। मैंने यह नहीं कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह दूसरे मंत्रालय के अंतर्गत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर उत्पादन हो। टैक्नीकल कठिनाई आ जाने की वजह से परेशानी हो रही है। उसमें विशेषज्ञ लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बेहतर उत्पादन वहां से हो सके। 1984-85 के लिए हमारा लक्ष्य 154 बिलियन यूनिट का है और नयी उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए हमारा लक्ष्य 3400 मैगावाट का है। इस उत्पादन क्षमता को जोड़ने के बाद ही हम छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 43 हजार मैगावाट तक पहुंचेंगे। हमें विश्वास है कि हम इस निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।...

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : यह कांट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है।——...

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Any side question, you need not reply to. You reply only to the main question. If you start answering all side question, it is not possible to conduct the House. It is not that every Member will go on putting questions always.

श्री आरिफ मोहम्मद खां: लक्ष्य तो हमें निर्धारित करना ही है। प्रदेश सरकारों से हम सम्पर्क बनाए रखते हैं और उनसे कहते हैं कि जहां कहीं उन्हें कठिनाई आ रही है, वह हमें बताए ताकि हम अपने विशेषज्ञों को भेजकर उन कठिनाइयों को दूर करा सकें। जहां तक प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में यदि पिछले साल लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके, हम यह सोच लें कि इस साल भी लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि तमाम लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। ऐसी हमें आशा है। हमने बहुत से नये कदम भी उठाये हैं और हम निश्चित तौर पर अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। जहां तक प्रश्न है कि कौन-कौन से नये कदम उठाये गए हैं—

For better utilisation of the existing generating capacity, a roving team/task force of Central Electricity Authority regularly visit thermal stations and devise time-bound action-plans fo rimprovement in generation. To expedite the commissioning of on-going projects, the Central Electricity Authority closely monitors construction activity and also assists in the timely delivery of equipment and spares by manufacturers/suppliers.

इसके अलावा श्रीमान् हमने अपने तमाम मौजूदा पावर स्टेशन्स को रैनोवेशन करने के लिए, उनको मोडर्नाइज बनाने के लिए, 500 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है जो सरकार के विचाराधीन है। इन 500 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल पुराने पावर स्टेशन्स का प्लान्ट लोड फैक्टर बेहतर करने के लिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। शर्मा साहब ने भी उसी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाया। यदि एक परसेंट भी प्लांट लोड़ बढ़ेगा तो उससे कितना फायदा होगा। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि रैनोवेशन और पावर स्टेशन्स का मोडर्नाइजेशन करने के बाद जो लाभ प्राप्त होगा, उतना शायद तीन गुना कीमत लगा कर भी नहीं प्राप्त हो सकता था। यदि हम जैनरेटिंग कैपेसिटी को संगठित करने पर ध्यान देते तो हमें इसके मुकाबले तीन या चार गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता।

इसके अलावा आपने कोयले के बारे में भी जानकारी चाही है हमारा कोल कम्पनियों से लगातार सम्पर्क है और हम समय-समय पर उसकी क्वालिटीज को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए बैठकें करते रहते हैं। इसके अलावा कोल कम्पनियों ने अपनी तरफ से कोल हैंडलिंग प्लांटस और क्रशर्स लगाये हुए हैं। कोयले की ग्रेडिंग के लिए कोल कम्पनियों ने कोल कन्ट्रोलर की भी नियुक्ति की है तथा कोयले की ज्वाइंट सैम्पलिंग करने के लिए ऊर्जा विभाग तथा कोयला विभाग दोनों के अधिकारी मिलकर काम करेंगे ताकि कोयले की क्वालिटी को सुनिश्चित किया जा सके।

यह ठीक है कि हमें बी. एच. ई. एल. के बारे में भी कभी-कभी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। जिस कारखाने के बारे में हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम वहां से सम्पर्क करके उनसे उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए कहते हैं। वे लोग शिकायतें दूर करने का प्रयत्न भी करते है। कुल मिलाकर हम यह समझते हैं कि स्थिति

अच्छी है और हर जगह से शिकायतें नहीं आ रही हैं, केवल कुछ एक शिकायतें हैं। बी. एच. ई. एल. से सम्बन्धित शिकायत का कारण यही है कि वह कारखाना नया है, जहां हम तजुर्बा और सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की नीति उस कारखाने को आगे बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने की है।

श्री मनोहर लाल सैनी (कुरुक्षेत्र) : मि. डिप्टी स्पीकर, सर, 19 तारीख को दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बिजली बिल्कुल बंद हो गई। वैसे तो मंत्री जी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपना वक्तव्य दे दिया है। अच्छा है शहर वालों को भी पहली बार पसीना आया। वैसे गांव में तो हमेशा ही बिजली बंद रहती है। मंत्री जी को भी उसका तजुर्बा होगा। खेतों को आप बिजली दे नहीं पा रहे हैं। देखने की बात यह है कि उन तमाम राज्यों में, उत्तर भारत के उन स्टेट्स में, जहां आप ही की पार्टी की सरकारें है, वैसे दिल्ली में भी आप ही की सरकार है, बिजली बंद हुई है। जहां यह सरकार दूसरे तमाम डिपार्टमेंट को चलाने में नाकामयाब सिद्ध हुई है, बिजली के मामले में भी निकम्मी साबित हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार को देख लीजिए, या हरियाणा की, सरकार को, सारी निकम्मी हैं। जितने भी वहां पावर स्टेशन्स बने हुए हैं, बोर्ड हैं, बिजली का जैनरेशन हो रहा है, उन सब में लास है। हर साल लासेज बढ़ते जा रहे हैं और उपभोक्ताओं से हर साल प्रति यूनिट के दाम बढ़ाये जा रहे हैं।

13.hrs.

अभी बिजली मंत्रियों की मीटिंग हुई और छठी योजना समाप्त होने जा रही है, सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। आपने बताया 43,000 मेगावाट बिजली की क्षमता हासिल की है। ऐक्चुअल जैनरेशन कितना है, और कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद यह क्षमता हासिल की है? और इसमें कितनी आप ऐग्रीकल्चर सैक्टर को दे रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रियल सैक्टर को दे रहे है और कितनी शहरों तथा गांवों को दे रहे है? कोई योजना सरकार के पास है या सातवीं योजना में आप बनाने जा रहे हैं? तथा वितरण का तरीका है कि उस बिजली में से कितना ऐग्रीकल्चर सैक्टर और रूरल सैक्टर को देंगे? और पावर सप्लाई अनइन्टरप्टेड हो इसको कैसे ऐनश्योर करेंगे?

अगर 19 तारीख की घटना नहीं होती तो आपकी सरकार का ध्यान सम्भवतः बिजली की तरफ नहीं जाता। यह किन कारणों से हुआ इसके लिए आपने एक समिति बनाई है। यह समिति के चेयरमैन को मालूम है क्योंकि वही सारे सिस्टम को रन कर रहे हैं और उनके आदमी ही जिम्मेदार होंगे। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव फैल्योर है जिसमें आप और आपका मंत्रालय जिम्मेदार है कि आप ठीक ढंग से इस मंत्रालय को रन नहीं कर रहे हैं। शहरों में तो 19 तारीख को महसूस हुआ, लेकिन गांवों में तो हर रोज यह तकलीफ महसूस हो रही है जब कि बिजली के चार्जेज हर महीने आप उनसे ले लेते हैं। सारी कैपेसिटी शहरों में बांट देते हैं।

आपने कहा जैनरेशन बढ़ा है। ठीक है। लेकिन जैनरेशन इनस्टाल्ड कैपेसिटी कितनी है और कितना ऐक्चुअल जैनरेशन हो रहा है, किस कोस्ट पर हो रहा है और कितना रूरल सैक्टर को प्राइस पर दे रहे

(श्री मनोहरलाल सैनी)

हैं ? भविष्य में क्या आप यह भी ध्यान रखेंगे कि केवल शहरों की तरफ ही नहीं गांवों को भी अनइन्टरप्टेड सप्लाई मिले इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है, इसको बताने की मंत्री जी कृपा करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सवाल माननीय सदस्य ने ऐसे उठाये हैं जिनका सीधे विषय से संबंध नहीं है। जो आंकड़े इस वक्त मेरे पास हैं वह दे दूंगा और जो नहीं हैं वह मैं बाद में उनको उपलब्ध करा दूंगा। यह टैकनीकल कारणों से फैल्योर हुआ और इसकी जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति सरकार ने बनाई है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें सरकार दोषी है, शायद आपने निकम्मापन शब्द का इस्तेमाल किया। मेरे पास वह आंकड़े है जो मैं बता रहा हूं। 1974-75 में ऐक्चुअल प्लान्ट लोड फैक्टर बिजली उत्पादन का 52.5 प्रतिशत था, 1975-76 में 52.1 प्रतिशत था, 1976-77 में 55.9 प्रतिशत, 1977-78 में बड़ी क्रान्तिकारी घटना हुई जब आप पावर में आये उस साल 55 से घट कर लोड फैक्टर 51.4 प्रतिशत रह गया।

श्री मनोहर लाल सैनी : जब से आप गये हो बिजली बन्द हुई।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उसी साल की बात है। आपके मंत्री पद ने जो आपने मुझे दिया था वह भी मुझे आपके साथ नहीं रख सका। इसी निकम्मेपन की वजह से।

1977-78 में 51.4 प्रतिशत, 1978-79 में 48.3 प्रतिशत 1979-80 में 44.7 प्रतिशत यानी 55 प्रतिशत से घटकर 44.7 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर 3 साल के अन्दर आ गया। घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसमें आग लगाने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली काफी होती है। उसके बाद फिर उसका दोबारा निर्माण करना, उसमें कितना समय परिश्रम और मेहनत लगती है, इसकी कोई भी कल्पना कर सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जो उन्होंने पूछा, तो उनका कंजम्पशन कुल ऊर्जा उत्पादन का 16 प्रतिशत है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिये 22 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। 140 बिलियन यूनिट 1983-84 में कुल उत्पादन हुआ है।

श्री मनोहर लाल सैनी: सातवीं योजना में क्या देंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सातवीं योजना का कैसे बता दूं, उसे बन तो जाने दीजिए, मंजूर हो जाने दीजिये।

श्री राजेश कुमार सिंह : आरिफ साहब की भाषा सुनने में बड़ी मधुर और अच्छी लगती है। इन्होंने अपने शब्दों में बहुत सारे अलंकार जोड़े हैं। ये मेरे पुराने मित्र हैं, इनका मैं बड़ा अदब करता हूं।

इन्होंने यह बात कही कि मै हमने बहुत तरक्की की है, बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इन्होंने 43 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य बताया। मंत्री महोदय जानते होंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में बिजली का क्या लक्ष्य था और उसमें कितने लक्ष्य की पूर्ति

की गई। मेरा कहना यह है कि आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाये। आपको 7वीं योजना में 7 हजार मेगावाट बिजली अतिरिक्त उत्पादन करनी होगी।

आपने रीजनल ग्रिड सिस्टम बनाया। एक जरा सी घटना घटी और कितने ही प्रान्तों की बिजली नदारद, अंधकार हो गया। आप कहते हैं कि टैक्नीकल फाल्ट था। मान लेते हैं कि टैक्नीकल फाल्ट होगा, सैबोटाज नहीं हुआ, लेकिन आप इसे मानेंगे या नहीं कि एक जगह जरा सा फाल्ट हुआ कि कई प्रान्तों, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की बिजली चली गई। आपका सिस्टम कैसा है? इस पर आपको विचार करना चाहिये। आप बीच में फसे हुए हैं।

अभी विद्युत मंत्रियों की जो बैठक हुई, उसमें राज्याध्यक्ष कमेटी की सिफारिशों के सम्बन्ध में आप कोई निर्णय नहीं ले पाये। आप कोई निर्णय नहीं ले पायेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। मुझे इसमें संदेह हो रहा है।

रीजनल ग्रिड की बात आती है, आपने स्टैचुरी अथोरिटी की बात कही है। अभी तो इन्फार्मल एग्रीमेंट से काम हो रहा है। क्या आप यह सोच रहे हैं कि यह सिस्टम सही मायनों में काम करेगा। न्यूजपेपर में जो खबरें छपी हैं, उसके अन्तर्गत यह है कि आप एक्सपर्ट कमेटी बनाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यह चुनाव के बाद ही बनेगी, इससे पहले बनने वाली नहीं है।

आपको जानकारी है कि हिन्दुस्तान में बिजली की कमी के कारण खेतों में जब पानी चाहिए या फसल काटने के टाइम जब बिजली चाहिये तो वह मिल नहीं पाती है।

आपको जो हाई ईल्ड वाला प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें 20 हजार मेगावाट यूनिट का आपने लक्ष्य रखा हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो इसका प्लान क्या रहेगा? एक चर्चा प्लानिंग के बारे में हाउस में होनी चाहिये। मैं कई बार कह चुका हूँ कि यहां प्लानिंग के बारे में चर्चा बहुत कम हो पाती है। राज्याध्यक्ष कमेटी और मन्त्रियों की जो सिफारिशें हैं, उस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय लेना चाहिये। इसमें समय नहीं गुजारना चाहिये क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी 10 हजार करोड़ का नुकसान होता है। आप बिजली देते हैं, लोडिंग कम है, खेत में किसान बैठा है, उसको नुकसान होता है। मेरे छोटे से शहर में कांच वगैरह के उद्योग हैं। हम देखते है कि लोड न खींचे जाने की वजह से मजदूर बैठे रहते हैं।

ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों में बड़ी गड़बड़ी है। उत्तर प्रदेश में ओबरी थर्मल प्रोजेक्ट में 200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि उसकी कैपेसिटी 1550 मेगावाट है। यही हालत हरदुआगंज की है। वहां पर तीन यूनिट जल गए हैं। वहां पर 155 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश में 5.60 करोड़ यूनिट की जरूरत है, जबकि उसको सिर्फ 1.20 यूनिट देना तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्टेशनों से 3.20 करोड़ यूनिट प्राप्त होने चाहिए। नैशनल कार्पोरेशन के द्वारा 1.10 करोड़ यूनिट दिए जाते हैं। दोनों मिलाकर सिर्फ 1.20 लाख यूनिट देने की बात है।

(श्री राजेश कुमार सिंह)

बिजली के बारे में सरकार की कोई नेशनल पालिसी नहीं है। वह कहती है कि वितरण की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। इस बारे में एक निदिचित व्यवस्था करनी चाहिए। नेशनल ग्रिड बनाया जाए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि एक जगह कोई खामी हो और सारे देश में बिजली खत्म हो जाए। राजाध्यक्ष कमेटी की रीकमंडेशन्ज पर अमल करना चाहिए।

टैरिफ के भिन्न-भिन्न रेट हैं। हिन्दी लको से 11 पैसे प्रति-यूनिट लिया जाता है और किसानों से 26 पैसे पर यूनिट। इस बारे में एक निश्चित प्रणाली और एक निश्चित दर निर्धारित करने चाहिए।

यह ठीक है क केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर धदेश की मदद की जा रही है, मगर उसको 500 मेगावाट बिजली और दी जाए, वर्ना उसकी हालत बदतर हो जाएगी।

बी. एच.ई.एल. द्वारा बनाई गई मशीनों और एक्विपमेंट के बारे में शिकायतें हैं कि वह ठीक फंक्शन नहीं कर रहे हैं। क्या कोई विशेषज्ञ इस बारे में जांच कर रहे हैं; यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि देश में ये मशीनें बनाने से अनुभव प्राप्त होगा। देश के साथ इस तरह खिलवाड नहीं करना चाहिए। देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए बिजली की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए विदेशों से अच्छा एक्विपमेंट और मशीनें आयात करने चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि छठी योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारत किया गया है। प्लानिंग कमीशन ने हमारे लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि छटी पंच-वर्षीय योजना में हमने 19,600 मेगावाट की एडीशनल कैपेसिटी बनानी है। मिड-टर्म एप्रेजल में इसकी दोबरा समीक्षा की गई और संसाधनों के अभाव, कंस्ट्रेन्ट आफ रीसोर्सिज, के कारण इसको घटाकर 14,5000 मेगावाट कर दिया गया। हमें पूरी आशा है कि यह निर्धारित लक्ष्य पूरी कर लेंगे। (व्यवधान) हमने नहीं घटाया है। हमने तो पिछले साल 4,000 मेगावाट से कुछ आधिक बिजली ग्रिड में जोड़ दी है। और यह अपने आप में एक रेकार्ड था। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं इस देश देश के बाहर की जिन का ही न कहीं इस सहयोग होता है उन्हें थोड़ी देर के लिए इस पर बहुत आश्चर्य हुआ कि हमने अपनी यह क्षमता विकसित कर ली है कि हर साल 4 हजार से अधिक मेगावाट बिजली अपने सिस्टम में, अपनी व्यवस्था में जोड़ने में सफल हो गए हैं। अगर माननीय राजेश कुमार सिंह जी अपने गुड आफिसेज का इस्तेमाल करें और हमें और ज्यादा ससाधन दिलाए तो हम आप को विश्वास दिलाते हैं (व्यवधान)... सम्मानित सदस्य है सदन के आप कहेंगे तो उसका भी असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि योजना आयोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जो मध्य योजना समीक्षा हुई उस योजना आयोग ने उसको घटा कर 14650 मेगावाट कर दिया...,

एक माननीय सदस्य : वह पूरा कर लिया?

श्री आरिफ खां : उसको पूरा कर रहे हैं। इस वर्ष के अन्त तक, यानी छटी

पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हमें पूरी उम्मींद है कि वह लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

इस के अलावा आप ने हाइडल पावर के लिए ट्रांसमिशन की बात भी कही और कई एक बातें ऐसी हैं जिन पर आप आपकी चिन्ता वास्तविक है और हमें भी उस पर चिन्ता है। मैं ने पहले ही कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री, शिव शंकर जी ने न केवल राज्यों के विद्युत मंत्रियों की बैठक में चिन्ताव्यक्त की बल्कि पत्रों के माध्यम से भी उन्होने बार-बार इस तरफ राज्य विद्युत परिषदों का ध्यान दिलाया है और मिनिस्टर्स आफ एनर्जी जो स्टेट्स के हैं उन का ध्यान दिलाया हैं, उन से यह कहा है कि प्लान्ट लोड फैक्टर को बेहतर करें, उस की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाएं और इस के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से उन की आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध कराएं। इस ओर खास तौर से उन बयान बार बार दिलाया है और अभी भी जो सारी बातें से माननीय सदस्यों ने कही हैं जिन का सीधा सम्बन्ध राज्य विद्युत परिषदों से है, उनकी उन भावनाओं से हम राज्य विद्युत परिषदों को अवगत करा देंगे।

इस के अलावा चूंकि खास तौर से मैं ने पहले भी कहा कि पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में और दिल्ली में पूरे तौर से बिजली प्रभावित हुई थी, इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि दिल्ली में बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए कई एक कदम उठाए हैं जैसे मुरादनगर में जो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद जिले में है एक बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 840 मेगावाट की क्षमता का बनाने का हमने फैसला किया है। इसके अलावा 180 मेगावाट का गैस टर्बाइन यहां लगाने का फैसला किया गया है जो हमें उम्मीद है कि अगले एक वर्ष के अंदर पूरा कर देगें। इसके अलावा 67.5 मेगावाट की दो यूनिट्स राजघाट पावर स्टेशन जो पुरानी मशीनरी के कारण बन्द हो गया था, वहां उस पुराने प्लान्ट को रिप्लेस करने के लिए लगाने का फैसला किया गया हैं। इसके अलावा रिहैंड सुपर थर्मल पावर स्टेशन. सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन और नरौरा का ऐटामिट पावर प्लान्ट जो है इन में भी दिल्ली का शेयर है। हमें विश्वास है कि जैसे-जैसे ये बनते जाएगे वैसे वैसे न सिर्फ यहां जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार बिजली उपलब्ध होगी।

एक माननीय सदस्य : नरौरा में कब तक बन जायगा ? आपके ही जिले का है।

श्री आरिफमोहम्मद खां : मैं ने सिर्फ यही कहा कि उसमें भी दिल्ली का शेयर है।

श्री राजेश कुमार सिंह : उत्तर प्रदेश को दिलवाएगे या नहीं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उत्तर प्रदेश के लिए कहलवाइए नहीं, मेरे ख्याल से पहले ही उत्तर प्रदेश कुछ ज्यादा शेयर ले रहा है, वरना शिकायत का कारण हो जायेगा।

जैसा मैंने पहले कहा, आप ने जो सुझाव दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं

(श्री आरिफ मोहम्मद खां)

और हम ने उनको नोट कर लिया है। हम अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं...(व्यवधान)... टेरिफ के बारे में एक कमेटी बनाने का मामला विचाराधीन है जो इस को देखेगी कि टैरिफ में यह भिन्नता रहे या इस को किसी तरह कम या खत्म किया जा सकता है।

13.20 hrs.

STATEMENT *RE* RECENT DEVELOPMENTS IN JAMMU AND KASHMIR

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) ; Sir, in the State of Jammu and Kashmir certain elements had been indulging in anti-national and secessionist activities since the latter half of 1983. These activities were in the form of demonstrations speeches, hartals, slogan-mongering, causing bomb explosions and issuing threats to life and property of public men, media men and others.

Further, though All India Sikh Students Federation was declared an unlawful association in March 1984, its objectionable activities continued in the State. Other Sikh extremists also joined hands with them.

Following the action by security forces in Punjab, AISSF activists and other Sikh extremists made a common cause with anti-national, secessionist and communal elements in the State and indulged not only in making objectionable speeches and shouting anti-national slogans but also in arson, loot and other violent activities on a large-scale.

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : I am on a point of order. Here they are giving the explanation that the government was toppled by defection.

MR. DEPUTY SPEAKER : You cannot interfere like this. Please sit down. The Minister is making a *suo motu* statement.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : This is a sufficient proof.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is making a statement. This is already on the agenda. There is going to be a discussion. We are going to allow it.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Building housing Central Government establishments such as post offices, telephone exchanges, State Bank of India were made the targets of attack. Religious places were also attacked and desecrated.

Since July 1983, the Central Government had been impressing upon the State Government to take firm and effective action against the anti-national, sceessionist and extremist elements. Till June 1984, the Home Minister sent mine communications to the Chief Minister in this regard. However, the action taken by the State Government was inadecuate and often belated and, therefore, made litttle impect. The activities of these elements, therefore, continued unabated including the hijacking of an Indian Airlines Plane.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : The hijacking took place after the dismissal of the Farooq Abdullah Government..

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : In another development, the Governor of Jammu and Kashmir dismissed the Ministry headed by Dr Farooq Abdullah on 2.7.1974 and swore in Shri C.M. Shah as Chief Minister to form a new Government under the